(2) निर्यात के लिए पैकेजिंग सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम देश के विभिन्न भागों में आयोजित किये जाते हैं ताकि लघु उद्योग निर्यातकों को नवीनतम पैकेजिंग मानकों/तकनीकों से वाकिफ कराया जा सके । ये कार्यक्रम भारतीय पैकेजिंग संस्थान के सहयोग से आयोजित किये जाते हैं जो इस संबंध में आवश्यक विशेषज्ञता प्रदान करते हैं । यह विशेष एवं सामान्य उद्योग के कार्यक्रम हैं । यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 1978–79 से शुरू किये गये थे ।

(3) सरकार लघु उद्योग विनिर्माताओं/सत्ता निर्यातकों को तकनीकी एवं सत्ता प्रदान कर रही है ।

(4) सरकार ने गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया है जो कि लघु उद्योग विनिर्माताओं को देश में गुणवत्ता की जागरुकता को बढ़ाने के लिये दिया जाता है । यह पुरस्कार गुणवत्ता वाले उत्पादन को प्रोत्साहित करने में सहायक होगा और जिससे निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा । ये पुरस्कार वर्ष 1986 में शुरू किये गये थे ।

(5) आयात निर्यात नीति के तहत निर्यात गृह/व्यापार गृह/स्टार व्यापार गृह/सुपर व्यापार गृह के रूप में मान्यता देने के लिये अतिरिक्त बल लघु उद्योग उत्पादों के निर्यात पर दिया गया है ।

(6) इस के अतिरिक्त निर्यात आयात नीति 1992–97 में दिये गये प्रोत्साहन उद्योग निर्यातकों के लिये भी उपलब्ध हैं ।

Restructuring of BICP

8229. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether any final view has been taken in the matter of restructuring of Bureau of Industrial Costs and Prices;

(b) if so, the details thereof;

(c) the recommendations made by the group appointed in this behalf; and

(d) the action taken by Government on the recommendations?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) to (d) Government has not taken any final decision in the matter of restructuring of the Bureau of Industrial Costs and Prices (BICP). Government has not appointed any group in this behalf.

Persons benefited under P.M.'s Rozgar Yojna in Madhya Pradesh

8230. SHRI SURESH PACHOURI:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the total number of youth benefited under the Prime Minister's Rozgar Yojna in Madhya Pradesh as on the 31st March, 1995, district-wise;

(b) what is the total amount released to the State so far under the Prime Minister's Rozgar Yojna (PMRY) since its inception;

(c) whether Government are aware that Banks are not releasing in time the amount sanctioned to the youth under the Yojna in the State; and

(d) if so, what remedial steps Government propose to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) Under Prime Minister's Rozgar Yojana, 21840 persons were sanctioned loan during 1993-94 and 1994-95 respectively. District-wise details as furnished by the State Government is enclosed in Statement (See below).